अमेरिकी संसद में ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव पहली बार हुआ मंजूर

प्रस्ताव के पक्ष में 50, विरोध में 48 मत...संसद से राशि मांग रहे ट्रंप के लिए बड़ा झटका

वाशिंगटन। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन (सीनेट) ने ईरान विरोधी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए युद्ध शक्तियों से जुड़े प्रस्ताव को पहली बार मंजूरी दे दी। सीनेट ने युद्ध रोकने के लिए 10वीं बार प्रयास किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 तथा विरोध में 48 मत पड़े। निचले सदन से यह पहले ही मंजूर हो चुका है। उधर, प्रशासन ने संसद से युद्ध के बाद गोला-बारूद फिर जुटाने के लिए 80 अरब डॉलर मांगे हैं।

मतदान के वक्त सीनेट कार्रवाई।

हालांकि यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे व्हाइट हाउस की सैन्य रणनीति के खिलाफ अमेरिकी संसद (कांग्रेस) की बढ़ती नाराजी व सियासी दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति पर बहस छिड़ गई है। अमेरिकी सांसद युद्ध समाप्ति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों पर नजर रख रहे हैं। यह युद्ध शुरू करने का फैसला अमेरिकी प्रशासन ने लिया था लेकिन अब उसे संसद से धन की जरूरत है। पारित प्रस्ताव बड़ी हद तक प्रतीकात्मक है और इसे पूरी तरह कानून का दर्जा हासिल नहीं है। एजेंसी

अमेरिकी विदेश नीति का सबसे खराब फैसला

सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने कहा, उच्च सदन में बड़ी संख्या में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने अमेरिकी जनता के कथाए बार-बार ट्रंप और उनके युद्ध का साथ दिया। अमेरिकियों को ईरान में ट्रंप की ऐतिहासिक भूल का मूल्य चुकाना पड़ा है। उन्होंने कहा, इसे इतिहास में अमेरिकी विदेश नीति के अब तक के सबसे खराब निर्णयों में से एक के रूप में याद किया जाएगा।

चार रिपब्लिकन सीनेटरों ने भी पक्ष में की वोटिंग

युद्ध शक्तियों संबंधी प्रस्तावों के पक्ष में चार रिपब्लिकन सीनेटरों ने इस बार भी ट्रंप के खिलाफ मतदान किया। इनमें अलास्का से लिसा मुर्कोव्स्की, मेन से सुसान कॉलिन्स, केंटकी से रैंड पॉल और लुइसियाना से बिल कैसिडी शामिल हैं। पेनसिल्वेनिया से डेमोक्रेटिक सीनेटर जॉन फेटरमैन ने प्रस्ताव के विरुद्ध रहे। इसके तहत ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए अब संसद की मंजूरी लेनी होगी।

ईरानी एटमी स्थलों का निरीक्षण होकर ही रहेगा : आईएईए

टोक्यो। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने बुधवार को संकेत दिया कि एजेंसी निरीक्षक ईरान के परमाणु संवर्धन स्थलों का दौरा करेंगे जो युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिका-ईरान अंतरिम समझौते का एक मुख्य हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ग्रॉसी ने टोक्यो में कहा, समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परमाणु सामग्रियों और परमाणु केंद्रों से जुड़ी सभी गतिविधियों की निगरानी आईएईए करेगा। जाहिर है इसके लिए वहां जाकर निरीक्षण करना ही होगा। वह एक दिन बाद ही, एक सप्ताह बाद हो या 10 दिन बाद। यह महत्वपूर्ण है, भले ही कभी भी हो। यह होने वाला है। एजेंसी

10 एटम बमों जितनी सामग्री

गत वर्ष इस्राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद से तेहरान ने आईएईए निरीक्षकों को परमाणु स्थलों तक पहुंच सीमित कर दी थी। माना जाता है कि इन स्थलों पर ईरान ने इतना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम जमा कर रखा है कि उससे लगभग 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। हालांकि, ईरान लगातार यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

■ **होर्मुज से बाहर आए फंसे हुए तेल टैंकर, आपूर्ति बढ़ी :** सिंगापुर। शिपिंग डाटा के मुताबिक, बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट से 50 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहे तीन फंसे हुए टैंकर बाहर निकले। इनमें से दो एशिया जा रहे थे। ईरान-अमेरिका अंतरिम समझौते से खाड़ी में फंसी आपूर्ति खुलने से वैश्विक कीमतें कम हो रही हैं। एजेंसी

विदेश संक्षेप

जर्मनी : संचार प्रणाली ठप, रेलें रुकीं फिर शुरू

बर्लिन। जर्मनी में संचार प्रणाली में खराबी से रेलवे नेटवर्क पर परिचालन बाधित हो गया। पूरे देश में रेल सेवाएं रोक दी गईं। हालांकि बुधवार को जर्मनी की ज्यादातर रेल सेवाएं सामान्य रूप से चलने लगीं लेकिन देर रात तक रही खराबी के चलते सिस्टम में खराबी के कारण देश भर में ट्रेनें और यात्री फंसे रहे। मुख्य रेल ऑपरेटर को अव्यवस्था के लिए आलोचना और सवालों का सामना करना पड़ा। एजेंसी

रूस-क्रीमिया में संपर्क काटने को निशाना

कीव। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में एक रेलवे पुल, एक ऊर्जा संयंत्र और दूसरे अहम आधारभूत ढांचों को निशाना बनाया। उसका मकसद चार साल से जारी युद्ध के नए चरण में रूस का संपर्क उसके कब्जे वाले इस अहम प्रायद्वीप से काटना रहा। यूक्रेन ने कहा, इन ड्रोन हमलों में काला सागर से घिरे इस प्रायद्वीप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एजेंसी

सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी बयानों को अनावश्यक बताकर भारत ने फटकारा

कहा, जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला था, है व हमेशा रहेगा

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने चीन और पाकिस्तान द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की अनावश्यक टिप्पणी की कड़ी निंदा की। भारत ने कहा, यह केंद्रशासित प्रदेश देश का पूरी तरह आंतरिक मामला है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर का मसला हमेशा से ही ऐसा रहा है, अब भी है और आगे भी रहेगा। बता दें, पाकिस्तान 2025 और 2026 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने 'कार्यान्वयन की खाई को पाटना : सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना' विषय पर परिषद की 'आरिया-फॉर्मूला' बैठक में ये टिप्पणी की। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद के जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद हरीश ने यह टिप्पणी की।

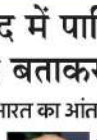
पी. हरीश

पीओके में विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र

भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर क्षेत्रों (पीओके) में लोगों के विरोध प्रदर्शनों को उसकी सुरक्षा एजेंसियां बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही हैं। भारत ने संकेत दिया कि मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड गंभीर सवालों के घेरे में है।

मंच के राजनीतिकरण का विकल्प चुना... भारत ने पाकिस्तान को फटकारते हुए कहा, उसने संयुक्त राष्ट्र मंच के सह-अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निष्पक्ष रूप से निर्वहन न करके अपने पद के दुरुपयोग से मंच का राजनीतिकरण किया है। उसने कहा, जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर भारत की किसी भी प्रकार की बाहरी टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। हरीश ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि एक सह-अध्यक्ष, जिसमें संतुलित व निष्पक्ष आचरण की अपेक्षा की जाती है, उसने इस मंच के राजनीतिकरण का विकल्प चुना।

संयुक्त राष्ट्र के पुराने मध्यस्थता ढांचे की समीक्षा हो : हरीश ने फलस्तीन का उदाहरण देकर कहा, दशकों से विभिन्न मध्यस्थता प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं निकला है। यह पुराने-अप्रासंगिक मध्यस्थता ढांचों की समीक्षा के लिए एक मजबूत आधार है। यह मानना सही नहीं है कि अध्याय-6 के तहत कोई मध्यस्थता व्यवस्था हमेशा लागू रहेगी। परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर नई दिल्ली की दावेदारी को कई देशों का समर्थन है। यूएन को इसके प्रयास करने होंगे।

गोपनीय होती हैं आरिया फॉर्मूला बैठकें : 'आरिया-फॉर्मूला' बैठकें अनौपचारिक और गोपनीय बैठकें होती हैं जिनमें सुरक्षा परिषद के सदस्य और आमंत्रित प्रतिभागी देश लचीली व्यवस्था में विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। इस प्रारूप का नाम वेनेजुएला के पूर्व राजदूत डिएगो आरिया के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 1992 में इसकी शुरुआत की थी।

एंथ्रोपिक : मायथॉस मॉडल ने अमेरिकी गोपनीय सिस्टम भेदा

अमेरिकी सरकार प्रणाली की ढूंढ निकालीं खामियां

वाशिंगटन। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि एआई कंपनी एंथ्रोपिक के मायथॉस मॉडल ने अमेरिकी सरकार के बेहद गोपनीय सिस्टम में कई कमजोरियों को कुछ ही घंटों में खोज लिया। उसने बेहद सुरक्षित-संवेदनशील कंप्यूटर सिस्टम को भेदकर ये खामियां ढूंढी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने मायथॉस का इस्तेमाल करके परीक्षण के तौर पर यह काम किया। इन कमजोरियों का पता करने का अर्थ यह नहीं रहा कि मॉडल ने उनका लाभ भी उठाया। अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि यह परीक्षण प्रोजेक्ट ग्लास्वॉर्म नाम की एंथ्रोपिक की एक पहल के तहत किया गया था। इस पहल में बड़ी टेक कंपनियों और दूसरी कंपनियों को साथ लाया गया, ताकि दुनिया के अहम सॉफ्टवेयर को उस गंभीर खतरे से बचाया जा सके जो मायथॉस मॉडल से सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को हो सकता था। वर्जीनिया के डेमोक्रेट सीनेटर मार्क वार्नर ने बैंकिंग, हाउसेस और शहरी मामलों की सीनेट समिति के सामने इई सुनवाई के दौरान सिस्टम्स के इस परीक्षण का खासतौर पर उल्लेख भी किया। एजेंसी

गोपनीय सिस्टम में सेंध : सीनेटर वार्नर

वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर ने यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी व अमेरिकी साइबर कमांड प्रमुख नेवल जोशुआ रुड के हवाले से देते हुए कहा, इस टूल ने हमारे लगभग सभी गोपनीय सिस्टम में सेंध लगा दी - हफ्तों में नहीं, बल्कि घंटों में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक ईमेल में इस मामले पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। एंथ्रोपिक ने भी कुछ नहीं कहा।

कांगो-यूगांडा के बाद अब फ्रांस में भी इबोला की पुष्टि

पेरिस। एजेंसी। इबोला इन दिनों वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। कांगो और यूगांडा से फैला ये संक्रमण दूसरे देशों के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इबोला के मामलों की संख्या बढ़कर 1,048 हो गई है इसमें 267 लोगों की मौत भी शामिल हैं। रविवार तक के डेटा के अनुसार 371 मरीज आइसोलेशन या हॉस्पिटल में भर्ती थे, जबकि 112 लोग ठीक हो गए थे। कुल मृत्यु दर 25.5 फीसदी था। कांगो और यूगांडा के बाद अब इबोला दूसरे देशों की ओर भी बढ़ता दिख रहा है।

जटिल हालात में समान विचार वाले देशों का साथ आना जरूरी : जयशंकर

संवाद न्यूज एजेंसी। दिल्ली/सियोल।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात में समान विचारधारा वाले देशों का साथ आना जरूरी है। जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो हयून के बीच बुधवार को सियोल में करीब तीन घंटे चली द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, तकनीक और वैश्विक आपूर्ति शृंखला सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के शुरुआती संबोधन में जयशंकर ने कहा, मौजूदा समय में दुनिया काफी मुश्किल व जटिल दौर में है। ऐसे में जरूरी है कि भारत और दक्षिण कोरिया जैसे समान विचारधारा वाले देश साथ आएं व मिलकर काम करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोनों देशों के रिश्तों में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं और भारत इसे पूरी तरह साकार करने को प्रतिबद्ध है।

PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS") NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES OF SKY ALLOYS AND POWER LIMITED ON THE MAIN BOARD OF STOCK EXCHANGES, BEING THE BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

(Please scan this QR to view the DRHP and the Draft Abridged Prospectus)

SKY ALLOYS AND POWER LIMITED

The Company was incorporated as 'Sky Alloys and Power Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated May 19, 2009 issued by the Registrar of Companies, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Subsequently, the Company was converted to a public limited company pursuant to a special resolution passed by Shareholders of the Company at the Extra-ordinary General Meeting held on September 12, 2022 under the name and style of 'Sky Alloys and Power Limited", and a fresh certificate of incorporation dated October 11, 2022 was issued by the RoC. For further details relating to the changes in the name and registered office of the Company, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 260 of the DRHP.

Registered Office: House No. 16, Recreation Road, Choubey Colony, Raipur, 492 001, Chhattisgarh, India.

Contact Person: Shalaka Modi, Company Secretary and Compliance Officer

Telephone: +91 77 14046097 | **Email:** compliance@skyalloys.co.in | **Website:** www.skyalloys.co.in | **Corporate Identity Number:** U27100CT2009PLC021184

OUR PROMOTERS: RAVI SINGHAL, SANDEEP AGRAWAL, NISHA SINGHAL, VIKAS AGRAWAL AND VINAY KUMAR AGRAWAL

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 17,891,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SKY ALLOYS AND POWER LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 16,084,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY THE COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 1,807,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING TO UP TO ₹ [●] MILLION ("OFFERED SHARES") BY RAVI SINGHAL AND NISHA SINGHAL ("THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS) ("OFFER FOR SALE", AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE OFFER"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% OF THE POST-OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THE COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT AGGREGATING UP TO 1,700,000 EQUITY SHARES, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY THE COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER AND ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THE COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT THE COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT IN LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. THE UTILIZATION OF THE PRE-IPO PROCEEDS BEING DISCRETIONARY IN NATURE, IF RAISED, SHALL BE COMPLETELY ATTRIBUTED / ADJUSTED TOWARDS THE GENERAL CORPORATE PURPOSES ("GCP") PORTION, UNLESS THE PRE-IPO PROCEEDS HAVE BEEN UTILISED TOWARDS THE DISCLOSED SPECIFIC OBJECTS OF THE OFFER. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND PROSPECTUS.THE PRICE BAND, THE MINIMUM BID LOT, IF ANY WILL BE DECIDED BY THE COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMs, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, ALL EDITIONS OF [●], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITIONS OF [●], (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF CHHATTISGARH, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, the Company, in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, may extend the Bid/Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the Book Running Lead Managers and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**"), other Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

This Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process and is in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein in terms of Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations, not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", and such portion, the "**QIB Portion**") provided that the Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which 40% shall be reserved in the following manner (i) 33.33% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds; and (ii) 6.67% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for Life Insurance Companies and Pension Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds, Life Insurance Companies and Pension Funds, as applicable, at our above the Anchor Investor Allocation Price. Any under-subscription in the Life Insurance Companies and Pension Funds category specified in (ii) above may be allocated to domestic Mutual Funds, in accordance with SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the remaining QIB Portion ("**Net QIB Portion**"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Funds Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIB. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹0.20 million and up to ₹1.00 million; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("**RIBs**") in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Retail Portion**"), subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further all potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective bank accounts (including UPI ID for UPI Bidders using UPI Mechanism) (as defined hereinafter) in which the Bid amount will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Banks, as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion of the Offer through the ASBA process. For details, see ***"Offer Procedure"*** on page 456 of the DRHP.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions on June 24, 2026 and other considerations, an initial public offer of its Equity Shares pursuant to the issue and has filed the DRHP dated June 22, 2026 with SEBI and the Stock Exchanges.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of publication of the public announcement, by hosting it along with the draft abridged prospectus on the website of the company at www.skyalloys.co.in, website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, respectively and the website of the BRLMs, i.e. Gretex Corporate Services Limited at www.gretexcorporate.com, and Arihant Capital Markets Limited at www.arihantcapital.com, the Company hereby invites the public to provide comments on the DRHP filed with SEBI and Stock Exchanges with respect to disclosures made therein. The public is requested to send a copy of their comments sent to SEBI, to the Company and the Company Secretary and Compliance Officer of the Company and/or the BRLMs and the Registrar to the Issue at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by the Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer of the Company on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of publication of this public announcement in accordance with Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors shall rely on their own examination of the Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 30 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP dated June 22, 2026 may only be taken after the Red Herring Prospectus ("**RHP**") has been filed with the ROC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP are proposed to be listed on the mainboard of Stock Exchanges.

For details of the share capital, capital structure and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of the Company, please see the section titled ***"Capital Structure"*** on page 97 of the DRHP. The liability of the members of the Company is limited by their shares. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 260 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED **Address:** A-401, Floor 4th, Plot FP-615, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near Indiabulls, Dadar (W), Delisle Road, Mumbai-400013, Maharashtra, India **Telephone:** 022 69308500 **E-mail:** mbd@gretexgroup.com **Investor Grievance E-mail:** info@gretexgroup.com **Website:** www.gretexcorporate.com **Contact Person:** Pradip Agarwal/ Rishika Rander **SEBI Registration Number:** INM000012177	**ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED** **Address:** 1011, Solitaire Corporate Park Building No.-10, 1st Floor, Guru Hargovindji Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093 **Telephone:** +91 22 4225 4800 **E-mail:** mbd@arihantcapital.com **Investor Grievance E-mail:** mbd@arihantcapital.com **Website:** www.arihantcapital.com **Contact Person:** Amol Kshirsagar / Satish Kumar Padmanabhan **SEBI Registration Number:** INM000011070	**MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** ***(formerly Link Intime India Private Limited)*** **Address:** C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India **Telephone:** +91 810 811 4949 **E-mail:** skyalloys.ipo@in.mpms.mufg.com **Investor Grievance E-mail:** skyalloys.ipo@in.mpms.mufg.com **Website:** www.in.mpms.mufg.com **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration Number:** INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFER

Shalaka Modi, Company Secretary and Compliance Officer

Registered Office : House No. 16, Recreation Road, Choubey Colony, Raipur 492001, Chhattisgarh, India.

Tel No: +91 771 4046097 | **Email:** compliance@skyalloys.co.in

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For Sky Alloys and Power Limited
On Behalf of Board of Directors
Sd/-
Shalaka Modi
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Raipur
Date: June 24, 2026

Disclaimer: **SKY ALLOYS AND POWER LIMITED** is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an Initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated June 22, 2026 with SEBI and the Stock Exchanges on June 24, 2026. The DRHP is available on the website of the company at www.skyalloys.co.in, SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e. Gretex Corporate Services Limited and Arihant Capital Markets Limited at www.gretexcorporate.com and www.arihantcapital.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a High degree of risk and for details relating to such risk, see ***"Risk Factors"*** on page 30 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, when filed, for making investment decision.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. The Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("**U.S. Securities Act**") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Company has not registered and does not intend to register under the U.S. Investment Company Act of 1940 ("Investment Company Act"). Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) to persons in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, in each case that are both "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and "qualified purchasers" as defined under the Investment Company Act in transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act and in reliance on Section 3(c)(7) of the Investment Company Act and (ii) outside the United States to non-U.S. persons in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

AdBaaz

नवभारत APPOINTMENT

भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड
RESERVE BANK OF INDIA SERVICES BOARD

विज्ञापन सं. आरबीआई/सर्वी/बीए/02/2026-27

भारतीय रिज़र्व बैंक में पूर्णकालिक अनुबंध आधार पर साइट इंजीनियरों की लैटरल भर्ती

भारतीय रिज़र्व बैंक में निम्नलिखित पदों के लिए पूर्णकालिक अनुबंध आधार पर साइट इंजीनियरों की लैटरल भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

विभाग का नाम – परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय				
क्रम संख्या	पद का नाम	स्तर/वेतन (समतुल्य ग्रेड)	रिक्तियों की संख्या	कार्य का स्थान*
1	पदनामीदार साइट इंजीनियर (सिविल)	स्तर – 2 (ग्रेड 'बी')	1	रायपुर
2	पदनामीदार साइट इंजीनियर (सिविल)	स्तर – 3 (ग्रेड 'सी')	6	चंडीगढ़/ जम्मू/ श्रीनगर/ मुंबई
3	पदनामीदार साइट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)	स्तर – 3 (ग्रेड 'सी')	1	मुंबई
	कुल	–	8	–

* चयनित उम्मीदवारों को बैंक की आवश्यकता के अनुसार बैंक के किसी भी प्रोजेक्ट में तैनात किया जा सकता है, यही उम्मीदवारों द्वारा चयनित कार्य का स्थान हुआ भी हो।

2. अन्य सभी नियमों जैसे पात्रता मानदंड, रिक्तियों के आरक्षण, चयन योजना, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और अन्य अनुदेशों के लिए कृपया **29 जून 2026** को बैंक की वेबसाइट (**www.rbi.org.in**) पर प्रकाशित होने वाले विस्तृत विज्ञापन को देखें। उम्मीदवार उक्त पदों के लिए केवल बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं।
3. आवेदनों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए तथा **29 जून 2026 से 20 जुलाई 2026** आवेदन शुल्कों/सूचना प्रभारों के भुगतान हेतु विंडो (समय: 06:00 बजे तक)

टिप्पणी:
(i) बोर्ड की इन रिक्तियों में किसी भी तरह के परिवर्तन या अधिकार है।
(ii) उक्त विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (**www.rbi.org.in**) प